



Microfinance Institutions Network (MFIN)
MFIN organises Uttarakhand FINCLAVE 2018
Coverage Report
12th April 2018

Submitted By:
Perfect Relations

Media Coverage Index

S. No.	Publication Name	Media
1.	Dainik Jagran	Print
2.	Dainik Jagran (I-Next)	Print
3.	Amar Ujala	Print
4.	Hindustan	Print
5.	Rashtriya Sahara	Print
6.	Abhijan Times	Print
7.	Shah Times	Print
8.	Dainik Hawk	Print
9.	Dainik Prabhat	Print
10.	Dehradun Times	Print
11.	Dainik Savera	Print
12.	Himachal Times	Print
13.	Jan Aagaj	Print
14.	News Detail	Print
15.	Jan Bharat Mail	Print
16.	Doon Darpan	Print
17.	Garhwal Post	Print
18.	Action India	Print
19.	Saksham Uttarakhand	Print
20.	Pradhan Times	Print
21.	Veer Arjun	Print
22.	Uttar Bharat Live	Print
23.	Gadh Samvedna	Online
24.	Pehchan Express	Online
25.	News Detail	Online

Executive Summary

The objective of organising a conclave in Dehradun was to highlight the contribution of microfinance companies in furthering the agenda of financial inclusion in Uttarakhand. It aimed at bringing together all the stakeholders at one platform to initiate discussions around improving infrastructure and digital outreach to achieve universal financial inclusion.

Uttarakhand Finclave, 2018 was well received by the local media. The event was attended by over 32 media persons from 27 media houses that included journalists and camerapersons from Print and Online. We witnessed the presence of prominent publications like Hindustan, Amar Ujala, Dainik Jagran and Dainik Prabhat among others. The news has been carried by the publications such as Dainik Jagran, Amar Ujala, Hindustan and Prabhat among others.

PRINT COVERAGE

Publication	Dainik Jagran
Edition	Dehradun
Date	13 th April, 2018
Page No.	07

सर्विस सेक्टर अभी पूर्ण रूप से विकसित नहीं

जागरण संवाददाता, देहरादून: माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट्स नेटवर्क (एमएफआईएन) की ओर से गुरुवार को हरिद्वार रोड स्थित एक होटल में वित्तीय समावेशन पर राज्य के पहले सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें 'उत्तराखंड में वित्तीय समावेशन की प्रगति और परिदृश्य' पर चर्चा की गई।

सम्मेलन में उत्तराखंड के सचिव (फाइनेंस) अमित सिंह नेगी ने कहा कि भारत में सर्विस सेक्टर अभी पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुआ है। राज्य में पर्यटकों, खासकर विदेशी पर्यटकों की संख्या, हॉटेल-कल्चर को बढ़ावा मिलने से सर्विस सेक्टर को विकसित किया जा सकता है। कहा कि पहाड़ की महिलाओं का कृषि में अहम योगदान है। इसलिए फाइनेंशियल इनक्लूजन में उन्हें महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। कार्यक्रम



सम्मेलन

- एमएफआईएन की ओर से उत्तराखंड फिनवलेव 2018 का आयोजन
- उत्तराखंड में वित्तीय समावेशन की प्रगति और परिदृश्य पर चर्चा

हरिद्वार रोड स्थित एक होटल में माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट्स नेटवर्क के सम्मेलन में बोलते वक्ता।

में आरबीआई देहरादून के निदेशक सुब्रत दास, नाबार्ड के सीजीएम डीएन मागर, उपाध्यक्ष-देवेश सचदेव पैनल में शामिल रहे। एमएफआईएन के अध्यक्ष राकेश दुबे ने बताया कि वर्तमान में उत्तराखंड वित्तीय समावेशन में देशभर में 12वें स्थान पर है। शिशु कैटेगरी लोन के तहत मुद्रा योजना ने प्रदेश में लगभग 500 करोड़ रुपये का लोन

बांटा है। एनबीएफसी-एमएफआई और स्मॉल फाइनेंस बैंकों ने साथ मिलकर कम आय वर्ग वाले ग्राहकों को 275 करोड़ रुपये के लोन बांटे हैं। एजीएम एसएलबीसी के रमेश कुमार पंत, मुद्रा एंड एमएफआईएन के बोर्ड सदस्य एनके मैनी, सिडबी के पूर्व डीएमडी संजय अग्रवाल, उत्तराखंड ग्रामीण बैंक के चेयरमैन संजय अग्रवाल, नेशनल

सैटिन क्रेडिट केयर नेटवर्क लिमिटेड के सीओओ देव वर्मा, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी गोविंद सिंह, एसबीआई देहरादून के डीजीएम सुबीर कुमार मुखर्जी ने भी विचार रखे। सम्मेलन के नॉलेज पार्टनर की ओर से यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी स्टडीज के डॉ. दीपांकर छाबड़ा, डॉ. सुमीत गुप्ता, डॉ. विनय शामिल हुए।

Publication	Dainik Jagran (I-Next)
Edition	Dehradun
Date	13 th April, 2018
Page No.	02

माइक्रो फाइनेंस से महिलाओं की उंची उड़ान

dehradun@inext.co.in

DEHRADUN (12 April) : मेहूवाला की बबीता, आईएसबीटी के पास रहने वाली संतोष और देहरादून के पास ही



एक गांव की पूनम आज हाउस वाइफ होने के साथ ही घर



बबीता



संतोष



पूनम

परिवार के साथ रहते हुए छोटा-छोटा बिजनेस कर बड़ा

उदाहरण पेश कर रही है. बबीता ने घर में ही सिलाई सेंटर लगाया है. अपने साथ ही वह आसपास रहने वाली एक दर्जन से अधिक महिलाओं को भी रोजगार दे रही है. संतोष ने फल की दुकान और पूनम भी सिलाई कारखाना लगाया है.

माइक्रो फाइनेंस से सफलता

ऐसी हजारों महिलाएं उत्तराखंड में छोटे-छोटे बिजनेस के जरिए अपनी कमाई शुरू कर लोगों के लिए उदाहरण बन गई हैं. यह संभव हुआ है माइक्रो फाइनेंस कंपनीज से मिले बिना गारंटी के लोन से. इन्हीं महिलाओं की सफलता की कहानी के साथ वेडनसडे को देहरादून में फाइनेंशियल इन्क्लूजन में माइक्रो फाइनेंस कंपनीज के योगदान को बढ़ाकर लोगों को स्वरोजगार उपलब्ध करा पहाड़ से पलायन रोकने पर उत्तराखंड फिनक्लेव 2018 नाम से मंथन हुआ. इसमें नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज और माइक्रो फाइनेंस संस्थाओं के प्रतिनिधियों समेत रिजर्व बैंक और सरकार के प्रतिनिधि शामिल हुए. माइक्रो फाइनेंस के जरिए सेल्फ डिपेंडेंट बनी महिलाओं ने सफलता की कहानी बताई कि कैसे निम्न आय वर्ग के लोगों को स्वरोजगार के लिए बिना गारंटी रिजर्व बैंक के निर्धारित रेट पर ऋण उपलब्ध करा स्वरोजगार उपलब्ध कराएगा. सम्मेलन में फाइनेंस स्रक्रेटरी अमित नेगी सुब्रत दास प्रादेशिक निदेशक आरबीआई और डीएन मागर सीजीएम नाबार्ड सम्मेलन में पैनलिस्ट रहे.

35 प्रतिशत गरीबी रेखा से नीचे

राज्य में 35 प्रतिशत से अधिक आबादी गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रही है. माइक्रोफाइनेंस इस वर्ग के बिना गिरवी के लोन उपलब्ध कराने का महत्वपूर्ण स्रोत है. यहां तक कि सरकारी स्कीम मुद्रा भी एनबीएफ सी-एमएफआई का इस्तेमाल एक महत्वपूर्ण चैनल के तौर पर करता है. उत्तराखंड में 31 नियमित वित्तीय संस्थान हैं. जिसमें 10 एनबीएफ सी-एमएफ आइ और 3 स्मॉल फाइनेंस बैंक शामिल हैं.



सम्मेलन में मौजूद एक्सपर्ट्स एवं लोग.

यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी स्टडीज इस सम्मलेन का नॉलेज पार्टनर रहा.

फाइनेंशियल इन्क्लूजन में उत्तराखंड 12 वां स्थान

क्रिसिल इन्क्लूसिव्स 2018 की रिपोर्ट के अनुसार सबसे नया राज्य होने के बावजूद उत्तराखंड वर्तमान में वित्तीय समावेशन के मामले में देश में 12वें स्थान पर है. पहाड़ी जिलों में 70 प्रतिशत आबादी तक वित्तीय सेवाओं तक आसान पहुंच अभी भी उपलब्ध नहीं

है. वित्तीय सेवाएं प्रदान करने में अधिक खर्च और वित्तीय साक्षरता का अभाव जैसी बाधाओं का सामना करने में माइक्रो फाइनेंस कंपनीज महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं. फेड्र सरकार की मुद्रा योजना में भी माइक्रो फाइनेंस कंपनियां मददगार हैं

डिस्कशन में सुब्रत दास प्रादेशिक निदेशक आरबीआई देहरादून और डीएन मागर सीजीएम नाबार्ड उत्तराखंड पैनलिस्ट रहे.

बैंकों का मिला सहयोग

उत्तराखंड में 31 नियमित वित्तीय संस्थान हैं जिसमें 10 एनबीएफ सी. एमएफआई और 3 स्मॉल फाइनेंस बैंक शामिल हैं. एनबीएफसी-एमएफआई का सकल लोन पोर्टफोलियो 327 करोड़ रुपये का है और यह 2 लाख घरों की जरूरतों को पूरा करते हैं. उत्तराखंड में वित्तीय समावेशन को राज्य में काम कर रहे बिजनेस कॉरेंस्पॉन्डेंट्स क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों एसएचजी और सहकारी बैंकों का भी सहयोग मिला है.

वित्तीय समावेशन में 12वें नंबर पर उत्तराखंड

उत्तराखंड की प्रति व्यक्ति की आय में बढ़ोतरी हुई है. पहाड़ी इलाकों में असमानताएं हैं जिन्हें सर्विस सेक्टर को बढ़ावा दे कर दूर किया जा सकता है. उन्होंने यह भी कहा कि पहाड़ी इलाकों में परिवार चलाने में महिलाओं का बड़ा योगदान है. जब हम फाइनेंशियल इन्क्लूसिव की बात करते हैं तो महिलाओं को महत्वपूर्ण स्थान देते हैं. अमित सिंह नेगी, सचिव फॉयनेंस

एनबीएफ सी-एमएफ आइज स्मॉल फाइनेंस बैंक और बैंकों जैसे वित्तीय संस्थानों ने राज्य में सरकार के वित्तीय समावेशन एजेंडा को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. विभिन्न रिपोर्टों के अनुसार सबसे नया राज्य होने के बावजूद उत्तराखंड वर्तमान में वित्तीय समावेशन के मामले में देश में 12वें स्थान पर है. राकेश दुबे, प्रेसिडेंट एमएफआईएन

Publication	Amar Ujala
Edition	Dehradun
Date	13 th April, 2018
Page No.	11

माइक्रो फाइनेंस के जरिए सुधरेगी राज्य की आर्थिकी

उत्तराखंड फिनक्लेव-2018 में विकास पर हुई चर्चा, पर्वतीय इलाकों में वित्तीय सेवाओं की कमी पर जताई चिंता

अमर उजाला ब्यूरो
देहरादून।

माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट्स नेटवर्क (एमएफआईएन) और उद्योग संगठन की ओर से बृहस्पतिवार को आयोजित कार्यशाला में वित्त विशेषज्ञों ने राज्य की वित्तीय स्थिति के साथ ही आर्थिक सुधारने समेत कई मुद्दों पर चर्चा की। वित्त विशेषज्ञों ने पर्वतीय इलाकों में वित्तीय सेवाओं की बेहद कम पहुंच पर चिंता जताते हुए इस पर अधिक फोकस करने पर जोर दिया।

आईएसबीटी स्थित एक होटल में उत्तराखंड फिनक्लेव-2018 के तहत 'उत्तराखंड में वित्तीय समावेशन की प्रगति और परिदृश्य' विषय पर आयोजित सेमिनार में राज्य में वित्तीय समावेशन की स्थिति व मौजूद चुनौतियों एवं

अवसरों पर भी चर्चा की गई। वित्त विशेषज्ञों ने निवेश को बढ़ावा देने में माइक्रो फाइनेंस एवं फिनटेक की भूमिका पर विमर्श किया। वित्त सचिव अमित सिंह नेगी ने कहा कि राज्य की आर्थिक नीतियों के चलते प्रति व्यक्ति की आय में बढ़ोतरी हुई है। इसके बावजूद पहाड़ी इलाकों में तमाम वित्तीय असमानताएं हैं। ये असमानताएं सर्विस सेक्टर को बढ़ावा देकर दूर की जा सकती हैं।

एमएफआईएन के अध्यक्ष राकेश दुबे ने कहा कि एनबीएफसी व एमएफआई जैसे स्मॉल फाइनेंस बैंक और वित्तीय संस्थानों ने राज्य में सरकार के वित्तीय एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। विभिन्न रिपोर्टों के अनुसार सबसे नया राज्य होने के बावजूद उत्तराखंड वर्तमान में वित्तीय समावेशन के मामले में देश



उत्तराखंड फिनक्लेव-2018 कार्यक्रम में पहुंचे लोग। अमर उजाला

में 12वें स्थान पर है। हालांकि यहां पहाड़ी जिलों में जहां 70 प्रतिशत आबादी निवास करती है वहां अभी

वित्तीय सेवाओं की पहुंच आसान नहीं है। वित्तीय संस्थान और लोग ऐसी ही कई बाधाओं से जूझ रहे

हैं। फिनटेक इन कठिनाइयों से पार पाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। माइक्रो फाइनेंस इस वर्ग के लिए औपचारिक ऋण का महत्वपूर्ण स्रोत है और यह बिना गिरवी के लोन उपलब्ध कराता है।

राज्य में शिशु कैटेगरी लोन के तहत मुद्रा ने लगभग 500 करोड़ रुपये का लोन बांटा है। सेमिनार को सुब्रत दास प्रादेशिक निदेशक आरबीआई, डीएन मागर सीजीएम नाबार्ड, राकेश दुबे प्रेसीडेंट एमएफआईएन, देवेश सचदेव, रमेश कुमार पंत एजीएम एसएलबीसी, एनके मैनी बोर्ड सदस्य मुद्रा, पूर्व डीएमडी सिडबी, संजय अग्रवाल, नवनीत कुमार, देव वर्मा, गोविंद सिंह, सुबीर कुमार मुखर्जी डीजीएम एसबीआई, डॉ. दीपांकर छाबरा, डॉ. सुमीत गुप्ता और डॉ. विनय समेत कई वित्त विशेषज्ञों ने संबोधित किया।

Publication	Hindustan
Edition	Dehradun
Date	13 th April, 2018
Page No.	08

वित्तीय सेवा मामले में आगे बढ़ रहा राज्य

देहरादून। माइक्रोफाइनेंस इंस्टीट्यूट्स नेटवर्क (एमएफआईएन) की ओर से 'उत्तराखंड में वित्तीय समावेशन की प्रगति और परिदृश्य' विषय पर सम्मेलन आयोजित किया गया। इस दौरान वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने की जरूरत बताई गई। वक्ताओं ने कहा कि नवोदित राज्य होने के बावजूद भी उत्तराखंड वित्तीय समावेशन (समाज पिछड़े एवं कम आय वाले लोगों को वित्तीय सेवाएं प्रदान करना) में अच्छे पायदान पर है।

गुरुवार को आईएसबीटी स्थित एक होटल में सम्मेलन का शुभारंभ वित्त सचिव अमित नेगी ने किया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी हुई है। पहाड़ी क्षेत्र होने से यहां असमानताएं बहुत हैं, जिन्हें दूर करने की जरूरत है। सर्विस सेक्टर को बढ़ावा देकर यह दूर हो सकती हैं।

Publication	Rashtriya Sahara
Edition	Dehradun
Date	13 th April, 2018
Page No.	04

सर्विस सेक्टर को बढ़ावा देने पर जोर

■ देहरादून (एसएनबी)।

देहरादून। माइक्रोफाइनेंस इंस्टीट्यूट्स नेटवर्क संस्थान व उद्योग संगठन के संयुक्त तत्वावधान में वित्तीय समावेशन विषय पर बृहस्पतिवार को फिनक्लेव-2018 कार्यशाला आयोजित हुई। सहारनपुर रोड

वित्तीय समावेशन पर आयोजित कार्यशाला में वक्ताओं ने रखी बात

स्थित एक होटल में आयोजित कार्यशाला में वित्त सचिव अमित नेगी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकात की। उन्होंने सर्विस सेक्टर को बढ़ावा देने की बात कही।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई है। पर्वतीय क्षेत्रों में कुछ असमानताएं हैं जिन्हें दूर करने का कोशिश

की जा रही है। सर्विस सेक्टर को बढ़ावा देकर इन असमानताओं को दूर किया जा सकता है। वित्तीय समावेशन में महिलाओं की अहम भागीदारी पर भी उन्होंने प्रकाश डाला। कहा कि वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में खड़ी चुनौतियों से पार पाने के लिए औद्योगिक संस्थानों को मिलजुलकर कार्य करना होगा।

माइक्रोफाइनेंस इंस्टीट्यूट्स नेटवर्क के प्रेसीडेंट राकेश दुबे ने कहा कि वित्तीय समावेशन के मामले में उत्तराखंड देश में 12वें स्थान पर है। इसको और भी बेहतर किया जा सकता है। उन्होंने वित्तीय साक्षरता पर भी जोर दिया। आरबीआई के क्षेत्रीय निदेशक सुब्रत दास व नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक डीएन मागर ने भी बतौर पैनलिस्ट कार्यशाला में शिरकात कर वित्तीय समावेशन पर अपनी बात रखी। वित्तीय संस्थानों में आपसी समन्वय पर भी उन्होंने जोर दिया। रमेश कुमार पंत,

एस्के मैत्री, संजय अप्पवाल, नवनीत शर्मा, दीपंकर छाबरा, डा. सुमित गुप्ता, डा. विनय देव वर्मा, गोविंद सिंह, सुबीर मुखर्जी, डा. आदि ने भी कार्यशाला में अपने विचार रखे।



कार्यशाला को सशोधित करता हुआ बतलाया।

Publication	Abhiyan Times
Edition	Dehradun
Date	13 th April, 2018
Page No.	08

उत्तराखंड में वित्तीय समावेशन की प्रगति और परिदृश्य पर सम्मेलन आयोजित

देहरादून। माइक्रोफाइनेंस इंस्टीट्यूट्स नेटवर्क (एमएफआईएन), एक स्व-विनामकीय संस्थान और उद्योग संगठन ने आज देहरादून में वित्तीय समावेशन पर राज्य के पहले सम्मेलन का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का मुख्य विषय था “उत्तराखंड में वित्तीय समावेशन की



प्रगति और परिदृश्य”। अमित सिंह नेगी, सचिव (फाइनेंस) ने सम्मेलन में विशेष संबोधन दिया। इस सम्मेलन का उद्देश्य राज्य में वित्तीय समावेशन की स्थिति का विश्लेषण करना था। साथ ही इसमें मौजूद चुनौतियों एवं अवसरों पर भी चर्चा की गई। वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने में माइक्रोफाइनेंस एवं फिन्टेक की भूमिका पर भी विचार-विमर्श हुआ। सुब्रत दास, प्रादेशिक निदेशक, आरबीआई देहरादून और डी.एन. मागर, सीजीएम नाबार्ड, उत्तराखंड सम्मेलन में पैनलिस्ट के तौर पर उपस्थित हुये। पैनल में शामिल होने वाले अन्य लोगों में राकेश दुबे, प्रेसिडेंट, एमएफआईएन और देवेश सचदेव, वाइस प्रेसिडेंट, एमएफआईएन थे। अमित सिंह नेगी, सेक्रेटरी (फाइनेंस), उत्तराखंड के कहा की प्रति व्यक्ति की आय में भद्रोत्तरी हुई है। उन्होंने यह भी कहा की पहाड़ी इलाकों में असमानताएं हैं जिन्हें दूर किया जा सकता है। उन्होंने यह भी कहा की असमानताएं को सर्विस सेक्टर को भरावा दे कर दूर किया जा सकता है। उन्होंने यह भी कहा की पहाड़ी इलाकों में महिलाओं का बड़ा योगदान है। इसीलिए जब हम फाइनेंसियल इन्क्लूसिव की बात करते हैं तो हम महिलाओं को महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। राकेश दुबे, एमएफआईएन के प्रेसिडेंट के अनुसार, “एनबीएफसी-एमएफआईएन, स्मॉल फाइनेंस बैंक और बैंकों जैसे वित्तीय संस्थानों ने राज्य में सरकार के वित्तीय समावेशन एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

Publication	Shah Times
Edition	Dehradun
Date	13 th April, 2018
Page No.	05

संक्षिप्त समाचार



सम्मेलन में अपने विचार व्यक्त करते हुए अथितिगण।

वित्तीय समावेशन पर पहला राज्य-केंद्रित सम्मेलन आयोजित

देहरादून। माइक्रोफाइनेंस इंस्टीट्यूट्स नेटवर्क (एमएफआईएन), एक स्व-विनामकीय संस्थान और उद्योग संगठन ने वित्तीय समावेशन पर राज्य के पहले सम्मेलन का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का मुख्य विषय था “उत्तराखंड में वित्तीय समावेशन की प्रगति और परिदृश्य”। अमित सिंह नेगी, सचिव (फाइनेंस) ने सम्मेलन में विशेष संबोधन दिया। इस सम्मेलन का उद्देश्य राज्य में वित्तीय समावेशन की स्थिति का विश्लेषण करना था। साथ ही इसमें मौजूद चुनौतियों एवं अवसरों पर भी चर्चा की गई। वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने में माइक्रोफाइनेंस एवं फिनटेक की भूमिका पर भी विचार-विमर्श हुआ। सुब्रत दास, प्रादेशिक निदेशक, आरबीआई और डीएन मागर, सीजीएम नाबार्ड, उत्तराखंड सम्मेलन में पैनलिस्ट के तौर पर उपस्थित हुये। पैनल में शामिल होने वाले अन्य लोगों में श्री राकेश दुबे, प्रेसिडेंट, एमएफआईएन और देवेश सचदेव, वाइस प्रेसिडेंट, एमएफआईएन थे। अमित सिंह नेगी, सेक्रेटरी (फाइनेंस), उत्तराखंड के कहा की प्रति व्यक्ति की आय में बढ़ोतरी हुई है छ उन्होंने यह भी कहा की पहाड़ी इलाकों में असमानताएं हैं जिन्हें दूर किया जा सकता है। उन्होंने यह भी कहा की असमानताएं को सर्विस सेक्टर को भरावा दे कर दूर किया जा सकता है।

Publication	Dainik Hawk
Edition	Dehradun
Date	13 th April, 2018
Page No.	02

उत्तराखंड फिनक्लेव 2018 का आयोजन

संवाददाता

देहरादून। माइक्रोफाइनेंस इंस्टीट्यूट्स नेटवर्क (एमएफआइएन), एक स्व-विनामकीय संस्थान और उद्योग संगठन, ने आज देहरादून में वित्तीय समावेशन पर राज्य के पहले सम्मेलन का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का मुख्य विषय था “उत्तराखंड में वित्तीय समावेशन की प्रगति और परिदृश्य”। अमित सिंह नेगी, सचिव (फाइनेंस) ने सम्मेलन में विशेष संबोधन दिया। इस सम्मेलन का उद्देश्य राज्य में वित्तीय समावेशन की स्थिति का विश्लेषण करना था। साथ ही इसमें मौजूद चुनौतियों एवं अवसरों पर भी चर्चा की गई। वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने में माइक्रोफाइनेंस एवं फिनटेक की भूमिका पर भी विचार-विमर्श हुआ। सुब्रत दास, प्रादेशिक निदेशक, आरबीआई देहरादून और डी.एन. मागर, सीजीएम नाबार्ड, उत्तराखंड सम्मेलन में पैनलिस्ट के तौर पर उपस्थित हुये। पैनल में शामिल होने वाले अन्य लोगों में राकेश दुबे,

प्रेसिडेंट, एमएफआइएन और श्री देवेश सचदेव, वाइस प्रेसिडेंट, एमएफआइएन थे। अमित सिंह नेगी, सेक्रेटरी (फाइनेंस), उत्तराखंड के कहा की प्रति व्यक्ति की आय में बढ़ोतरी हुई है छ उन्होंने यह भी कहा की पहाड़ी इलाकों में असमानताएं हैं जिन्हें दूर किया जा सकता है छ उन्होंने यह भी कहा की असमानताएं को सर्विस सेक्टर को भरावा दे कर दूर किया जा सकता है छ उन्होंने यह भी कहा की पहाड़ी इलाकों में महिलाओं का बड़ा योगदान है। इसीलिए जब हम फाइनेंसियल इन्क्लूसिव की बात करते हैं तो हम महिलाओं को महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। राकेश दुबे, एमएफआइएन के प्रेसिडेंट के अनुसार, “एनबीएफसी-एमएफआइज, स्मॉल फाइनेंस बैंक और बैंकों जैसे वित्तीय संस्थानों ने राज्य में सरकार के वित्तीय समावेशन एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। विभिन्न रिपोर्टों के अनुसार, सबसे नया राज्य होने के बावजूद, उत्तराखंड वर्तमान

में वित्तीय समावेशन के मामले में देश में 12वें स्थान पर है। हालांकि, यहां खासतौर से पहाड़ी जिलों में जहां 70 प्रतिशत आबादी निवास करती है, वित्तीय सेवाओं तक आसान पहुंच अभी भी उपलब्ध नहीं है, इस जरूरत को पूरा किया जाना जरूरी है।

वित्तीय संस्थानों और लोगों दोनों द्वारा कई बाधाओं का सामना किया जा रहा है, जैसेकि सेवाएं प्रदान करने में आने वाला अधिक खर्च और वित्तीय साक्षरता का अभाव आदि। इसके लिए खोजपरक समाधानों की जरूरत है। फिनटेक इन कठिनाईयों से पार पाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। “माइक्रोफाइनेंस की भूमिका के बारे में उन्होंने आगे कहा, “राज्य में 35 प्रतिशत से अधिक आबादी गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रही है। माइक्रोफाइनेंस इस वर्ग के लिए औपचारिक ऋण का महत्वपूर्ण स्रोत है और यह बिना गिरवी के लोन उपलब्ध कराता है। यहां तक कि, मुद्रा एनबीएफसी-एमएफआइ का इस्तेमाल एक महत्वपूर्ण चैनल के तौर पर करता

है ताकि शिशु कैटेगरी लोन के जरिये इन ग्राहकों तक पहुंचा जा सके। उत्तराखंड में, शिशु कैटेगरी लोन के तहत मुद्रा ने लगभग 500 करोड़ रुपये का लोन बांटा है। इसमें से, एनबीएफसी-एमएफआइ और स्मॉल फाइनेंस बैंकों ने साथ मिलकर कम आय वर्ग वाले ग्राहकों को 275 करोड़ रुपये के लोन वितरित किये हैं।” उत्तराखंड में 31 नियमित वित्तीय संस्थान हैं जिसमें 10 एनबीएफसी-एमएफआइ और 3 स्मॉल फाइनेंस बैंक शामिल हैं। एनबीएफसी-एमएफआइ का सकल लोन पोर्टफोलियो 327 करोड़ रुपये का है और यह 2 लाख घरों की जरूरतों को पूरा करते हैं। उत्तराखंड में वित्तीय समावेशन को राज्य में काम कर रहे बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट्स, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, एसएचजी और सहकारी बैंकों का भी सहयोग मिला है। इस सम्मेलन में एनबीएफसी-एमएफआइ, स्मॉल फाइनेंस बैंक, क्षेत्रीय बैंकों के प्रतिनिधि और नीति निर्माताओं आदि ने शिरकत की। इस सम्मेलन में आने वाले प्रमुख वक्ताओं में शामिल थे।

Publication	Dainik Prabhat
Edition	Dehradun
Date	13 th April, 2018
Page No.	03

एमएफआइएन ने उत्तराखंड फिनक्लेव का किया आयोजन

सम्मेलन का उद्देश्य राज्य में वित्तीय समावेशन की स्थिति का विश्लेषण करना रहा

देहरादून (प्रभात)

माइक्रोफाइनेंस इंस्टीट्यूट्स नेटवर्क (एमएफआइएन), एक स्व-विनामकीय संस्थान और उद्योग संगठन, ने आज देहरादून में वित्तीय समावेशन पर राज्य के पहले सम्मेलन का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का मुख्य विषय था "उत्तराखंड में वित्तीय समावेशन की प्रगति और परिदृश्य"। अमित सिंह नेगी, सचिव (फाइनेंस) ने सम्मेलन में विशेष संबोधन दिया। इस सम्मेलन का उद्देश्य राज्य में वित्तीय समावेशन की स्थिति का विश्लेषण करना था। साथ ही इसमें मौजूद चुनौतियों एवं अवसरों पर भी चर्चा की गई। वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने में माइक्रोफाइनेंस एवं फिनटेक की भूमिका पर भी विचार-विमर्श हुआ।

सुब्रत दास, प्रादेशिक निदेशक, आरबीआई देहरादून और डी.एन. मांगर, सीजीएम नाबार्ड, उत्तराखंड सम्मेलन में पैनलिस्ट के तौर पर उपस्थित हुये। पैनल में शामिल होने वाले अन्य लोगों में राकेश दुबे, प्रेसिडेंट, एमएफआइएन और श्री देवेश सचदेव, वाइस प्रेसिडेंट, एमएफआइएन थे।

अमित सिंह नेगी, सेक्रेटरी (फाइनेंस), उत्तराखंड के कहां की प्रति व्यक्ति की आय में बढ़ोतरी हुई है घा उन्होंने यह भी कहा की पहाड़ी इलाकों में असमानताएं हैं जिन्हें दूर किया जा सकता है। उन्होंने यह भी कहा की असमानताएं को सर्विस सेक्टर को भरावा दे कर दूर किया जा सकता है। उन्होंने यह भी कहा की पहाड़ी इलाकों में महिलाओं का बड़ा योगदान है। इसीलिए जब हम फाइनेंसियल इन्क्लूसिव की बात करते हैं तो हम महिलाओं को महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। राकेश दुबे, एमएफआइएन के प्रेसिडेंट के अनुसार, 'एनबीएफसी-एमएफ



सम्मेलन को संबोधित करते अमित नेगी सचिव (फाइनेंस)।

प्रभात

आइज, स्मॉल फाइनेंस बैंक और बैंकों जैसे वित्तीय संस्थानों ने राज्य में सरकार के वित्तीय समावेशन एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। विभिन्न रिपोर्टों के अनुसार, सबसे नया राज्य होने के बावजूद, उत्तराखंड वर्तमान में वित्तीय समावेशन के मामले में देश में 12वें स्थान पर है। हालांकि, यहां खासतौर से पहाड़ी जिलों में जहां 70 प्रतिशत आबादी निवास करती है, वित्तीय सेवाओं तक आसान पहुंच अभी भी उपलब्ध नहीं है, इस जरूरत को पूरा किया जाना जरूरी है। वित्तीय संस्थानों और लोगों दोनों द्वारा कई बाधाओं का सामना किया जा रहा है, जैसा कि सेवाएं प्रदान करने में आने वाला अधिक खर्च और वित्तीय साक्षरता का अभाव आदि। इसके लिए खोजपरक समाधानों की जरूरत है। फिनटेक इन कठिनाईयों से पार पाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। 'माइक्रोफाइनेंस की भूमिका के बारे में उन्होंने आगे कहा, "राज्य में 35 प्रतिशत से अधिक आबादी गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रही है।

माइक्रोफाइनेंस इस वर्ग के लिए औपचारिक गण का महत्वपूर्ण स्रोत है और यह बिना गिरवी के लोन उपलब्ध कराता है। यहां तक कि, मुद्रा एनबीएफसी-एमएफआइ का इस्तेमाल एक महत्वपूर्ण चैनल के तौर पर करता है ताकि शिशु कैटेगरी लोन के जरिये इन ग्राहकों तक पहुंचा जा सके। उत्तराखंड में, शिशु कैटेगरी लोन के तहत मुद्रा ने लगभग 500 करोड़ रुपये का लोन बांटा है।

इसमें से, एनबीएफसी-एमएफआइ और स्मॉल फाइनेंस बैंकों ने साथ मिलकर कम आय वर्ग वाले ग्राहकों को 275 करोड़ रुपये के लोन वितरित किये हैं।" उत्तराखंड में 31 नियमित वित्तीय संस्थान हैं जिसमें 10 एनबीएफसी-एमएफआइ और 3 स्मॉल फाइनेंस बैंक शामिल हैं। एनबीएफसी-एमएफआइ का सकल लोन पोर्टफोलियो 327 करोड़ रुपये का है और यह 2 लाख घरों की जरूरतों को पूरा करते हैं।

उत्तराखंड में वित्तीय समावेशन को राज्य में काम कर रहे बिजनेस करिस्पॉन्डेंट्स, क्षेत्रीय ग्रामीण

बैंकों, एसएचसी और सहकारी बैंकों का भी सहयोग मिला है।

इस सम्मेलन में एनबीएफसी-एमएफआइ, स्मॉल फाइनेंस बैंक, क्षेत्रीय बैंकों के प्रतिनिधि और नीति निर्माताओं आदि ने शिरकत की। इस सम्मेलन में आने वाले प्रमुख वक्ताओं में शामिल थे -रमेश कुमार पंत, एजीएम एसएलबीसी उत्तराखंड, एन.के. मैनी, बोर्ड सदस्य मुद्रा एंड एमएफआइएन और पूर्व डीएमडी, सिडबी; संजय अग्रवाल, चैयरमैन, उत्तराखंड ग्रामीण बैंक; नवनीत कुमार, वीपी, वित्तीय समावेशन एवं नये व्यावसाय, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया देव वर्मा, सीओओ, सैटिन फ्रेडिटेक केयर नेटवर्क लिमिटेड; श्री गोविंद सिंह, एमडी, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक और श्री सुबीर कुमार मुखर्जी, डीजीएम, एसबीआई देहरादून। यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी स्टडीज इस सम्मेलन का नॉलेज पार्टनर था। डॉ. दीपांकर छाबरा, डॉ. सुमीत गुप्ता और डॉ. विनययूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी स्टडीज के तरफ से इस सम्मेलन में शामिल थे।

Publication	Dehradun Times
Edition	Dehradun
Date	13 th April, 2018
Page No.	03



उत्तराखंड में वित्तीय समावेशन की प्रगति और परिदृश्य पर सम्मेलन आयोजित

देहरादून, संवाददाता। माइक्रोफाइनेंस इंस्टीट्यूट्स नेटवर्क (एमएफआईएन), एक स्व-विनामकीय संस्थान और उद्योग संगठन ने आज देहरादून में वित्तीय समावेशन पर राज्य के पहले सम्मेलन का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का मुख्य विषय था “उत्तराखंड में वित्तीय समावेशन की प्रगति और परिदृश्य”। अमित सिंह नेगी, सचिव (फाइनेंस) ने सम्मेलन में विशेष संबोधन दिया। इस सम्मेलन का उद्देश्य राज्य में वित्तीय समावेशन की स्थिति का विश्लेषण करना था। साथ ही इसमें मौजूद चुनौतियों एवं अवसरों पर भी चर्चा की गई। वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने में माइक्रोफाइनेंस एवं फिन्टेक की भूमिका पर भी विचार-विमर्श हुआ। सुब्रत दास, प्रादेशिक निदेशक, आरबीआई देहरादून और डी.एन. मागर, सीजीएम नाबार्ड, उत्तराखंड सम्मेलन में पैनलिस्ट के तौर पर उपस्थित हुये। पैनल में शामिल होने वाले अन्य लोगों में राकेश दुबे, प्रेसिडेंट, एमएफआईएन और देवेश सचदेव, वाइस प्रेसिडेंट, एमएफआईएन थे। अमित-सिंह नेगी, सेक्रेटरी (फाइनेंस), उत्तराखंड के कहा की प्रति व्यक्ति की आय में भड़ोतरी हुई है। उन्होंने यह भी कहा की पहाड़ी इलाकों में असमानताएं हैं जिन्हें दूर किया जा सकता है। उन्होंने यह भी कहा की असमानताएं को सर्विस सेक्टर को भरावा दे कर दूर किया जा सकता है। उन्होंने यह भी कहा की पहाड़ी इलाकों में महिलाओं का बड़ा योगदान है। इसीलिए जब हम फाइनेंसियल इन्क्लूसिव की बातकरते हैं तो हम महिलाओं को महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। राकेश दुबे, एमएफआईएन के प्रेसिडेंट के अनुसार, “एनबीएफसी-एमएफआईएन, स्मॉल फाइनेंस बैंक और बैंकों जैसे वित्तीय संस्थानों ने राज्य में सरकार के वित्तीय समावेशन एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। विभिन्न रिपोर्टों के अनुसार, सबसे नया राज्य होने के बावजूद, उत्तराखंड वर्तमान में वित्तीय समावेशन के मामले में देश में 12वें स्थान पर है।

Publication	Dainik Savera
Edition	Dehradun
Date	13 th April, 2018
Page No.	02

कार्यक्रम

उत्तराखण्ड में वित्तीय समावेशन की प्रगति और परिदृश्य पर सम्मेलन आयोजित

मौजूद चुनौतियों एवं अवसरों पर की गई चर्चा



वित्तीय समावेशन की प्रगति और परिदृश्य पर आयोजित सम्मेलन में मंचासीन वक्ता।

देहरादून, 12 अप्रैल (इंद्रजीत शर्मा) : माइक्रोफाइनेंस इंस्टीट्यूट्स नेटवर्क (एम.एफ.आई.एन.), एक स्व-विनियमकीय संस्वन और उद्योग संगठन ने देहरादून में वित्तीय समावेशन पर राज्य के पहले सम्मेलन का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का मुख्य विषय था 'उत्तराखण्ड में वित्तीय समावेशन की प्रगति और परिदृश्य'। अमिता सिंह नेगी, सचिव (फाइनेंस) ने सम्मेलन में विशेष संबोधन दिया। इस सम्मेलन का उद्देश्य

राज्य में वित्तीय समावेशन की स्थिति का विश्लेषण करना था। साथ ही इसमें मौजूद चुनौतियों एवं अवसरों पर भी चर्चा की गई। वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने में माइक्रोफाइनेंस एवं फिन्टेक की भूमिका पर भी विचार-विमर्श हुआ। सुब्रत दास, प्रदेशिक निदेशक, आरबीआई देहरादून और डॉ.एन. मागर, सीजीएम नाबार्ड, उत्तराखण्ड सम्मेलन में पैनेलिस्ट के तौर पर उपस्थित हुये। पैनेल में शामिल होने वाले अन्य लोगों में राकेश दुबे,

प्रेसिडेंट, एमएफआईएन और देवेश सचदेव, वाइस प्रेसिडेंट, एमएफआईएन थे। अमित सिंह नेगी, सेक्रेटरी (फाइनेंस), उत्तराखण्ड के कला की प्रति व्यक्ति की आय में भवोत्तरी हुई है। उन्होंने यह भी कहा की फाड़ी इलाकों में अस्मानतएव हैं जिन्हें दूर किंच जा सकता है। उन्होंने यह भी कहा की असमनतएव को सर्विस सेक्टर को भरावा दे कर दूर किंचना सकता है। उन्होंने यह भी कहा की फाड़ी इलाकों में महिलाओं का बड़ा योगदान

दून में 31 नियमित वित्तीय संस्थान

उत्तराखण्ड में 31 नियमित वित्तीय संस्थान हैं जिसमें 10 एनबीएफसी-एमएफआई और 3 स्मॉल फाइनेंस बैंक शामिल हैं। एनबीएफसी-एमएफआई का सकल लोन पोर्टफोलियो 327 करोड़ रुपये का है और यह 2 लाख घरों की जरूरतों को पूरा करते हैं। उत्तराखण्ड में वित्तीय समावेशन को राज्य में काम कर रहे विजनेस कॉरिस्पॉन्डेंट्स, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, एसएवजी और सहकारी बैंकों का भी सहयोग मिला है। इस सम्मेलन में एनबीएफसी-एमएफआई, स्मॉल फाइनेंस बैंक, क्षेत्रीय बैंकों के प्रतिनिधि और नीति निर्माताओं आदि ने शिरकत की। इस सम्मेलन में आने वाले प्रमुख वक्ताओं में शामिल थे रमेश कुमार पंत, एजीएम एसएलबीसी उत्तराखण्ड, एनके मैनी, बोर्ड सदस्य मुद्रा एंड एमएफआईएन और पूर्व डीएमडी, सिडबी; संजय अग्रवाल, देवरमैन, उत्तराखण्ड ग्रामीण बैंक; नयनीत कुमार, वीपी, वित्तीय समावेशन एवं नये व्यावसाय, नेशनल पैमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई); श्रीदेव वर्मा, सीओओ, सेंटिन क्रेडिटकेयर नेटवर्क लिमिटेड; गोविंद सिंह, एमडी, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक और सुधीर कुमार मुखर्जी, डीजीएम, एसबीआई देहरादून। युनिवर्सिटी अफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी स्टडीज इस सम्मलेन का नेतेज पार्टनर था व ड. दीपाकर छबरा, डा. सुमीत गुप्ता और ड. विनयकुनिवर्सिटी अफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी स्टडीज के तौर पर से इस सम्मलेन में शामिल थे।

है। इसीलिए जब हम फाइनेंसिकल इन्क्लूसिव की बात करते हैं तो हम महिलाओं को महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। राकेश दुबे, एमएफआईएन के प्रेसिडेंट के अनुसार, "एनबीएफसी-एमएफआईएन, स्मॉल फाइनेंस बैंक और बैंकों जैसे वित्तीय संस्थानों ने राज्य में सरकार के वित्तीय समावेशन एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए

महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। विभिन्न रिपोर्टों के अनुसार, सबसे नया राज्य होने के बावजूद, उत्तराखण्ड वर्तमान में वित्तीय समावेशन के मामले में देश में 12वें स्थान पर है। हालांकि, यहां खासतौर से फाड़ी जिलों में जहां 70 प्रतिशत आबादी निवास करती है, वित्तीय सेवाओं तक आसना बहुत अभी भी उपलब्ध नहीं है, इस जरूरत

को पूरा किया जाना जरूरी है। वित्तीय संस्थानों और लोगों दोनों द्वारा कई बाधाओं का सामना किया जा रहा है, जैसेकि सेवाएं प्रदान करने में आने वाला अधिक खर्च और वित्तीय साक्षरता का अभाव आदि। इसके लिए छोटे-मोटे समाधानों की जरूरत है। फिन्टेक इन कठिनाईयों से पार पाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभ सकती है।

Publication	Himachal Times
Edition	Dehradun
Date	13 th April, 2018
Page No.	03

उत्तराखंड फिनक्लेव 2018 का आयोजन

संवाददाता

देहरादून। माइक्रोफाइनेंस इंस्टीट्यूट्स नेटवर्क (एमएफआइएन), एक स्व-विनामकीय संस्थान और उद्योग संगठन, ने आज देहरादून में वित्तीय समावेशन पर राज्य के पहले सम्मेलन का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का मुख्य विषय था "उत्तराखंड में वित्तीय समावेशन की प्रगति और परिदृश्य"। अमित सिंह नेगी, सचिव (फाइनेंस) ने सम्मेलन में विशेष संबोधन दिया। इस सम्मेलन का उद्देश्य राज्य में वित्तीय समावेशन की स्थिति का विश्लेषण करना था। साथ ही इसमें मौजूद चुनौतियों एवं अवसरों पर भी चर्चा की गई। वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने में माइक्रोफाइनेंस एवं फिनटेक की भूमिका पर भी विचार-विमर्श हुआ। सुब्रत दास, प्रादेशिक निदेशक, आरबीआई देहरादून और डी.एन. माथर, सीजीएम नाबार्ड, उत्तराखंड सम्मेलन में पैनेलिस्ट के तौर पर उपस्थित हुये। पैनेल में शामिल होने वाले अन्य लोगों में राकेश दुबे,

प्रेसिडेंट, एमएफआइएन और श्री देवेश सचदेव, वाइस प्रेसिडेंट, एमएफआइएन थे। अमित सिंह नेगी, सेक्रेटरी (फाइनेंस), उत्तराखंड के कक्षा की प्रति व्यक्ति की आय में भद्रोत्तरी हुई है यह उन्होंने यह भी कहा की पहाड़ी इलाकों में असमानताएं हैं जिन्हें दूर किया जा सकता है यह उन्होंने यह भी कहा की असमानताएं को सर्विस सेक्टर को भरावा दे कर दूर किया जा सकता है यह उन्होंने यह भी कहा की पहाड़ी इलाकों में महिलाओं का बड़ा योगदान है। इसीलिए जब हम फाइनेंसियल इन्क्लूसिव की बात करते हैं तो हम महिलाओं को महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। राकेश दुबे, एमएफआइएन के प्रेसिडेंट के अनुसार, "एनबीएफसी-एमएफआइएन, स्मॉल फाइनेंस बैंक और बैंकों जैसे वित्तीय संस्थानों ने राज्य में सरकार के वित्तीय समावेशन एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। विभिन्न रिपोर्टों के अनुसार, सबसे नया राज्य होने के बावजूद, उत्तराखंड वर्तमान

में वित्तीय समावेशन के मामले में देश में 12वें स्थान पर है। हालांकि, यहां खासतौर से पहाड़ी जिलों में जहां 70 प्रतिशत आबादी निवास करती है, वित्तीय सेवाओं तक आसान पहुंच अभी भी उपलब्ध नहीं है, इस जरूरत को पूरा किया जाना जरूरी है।

वित्तीय संस्थानों और लोगों दोनों द्वारा कई बाधाओं का सामना किया जा रहा है, जैसेकि सेवाएं प्रदान करने में आने वाला अधिक खर्च और वित्तीय साक्षरता का अभाव आदि। इसके लिए खाजपरक समाधानों की जरूरत है। फिनटेक इन कठिनाइयों से पार पाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। "माइक्रोफाइनेंस की भूमिका के बारे में उन्होंने आगे कहा, "राज्य में 35 प्रतिशत से अधिक आबादी गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रही है। माइक्रोफाइनेंस इस वर्ग के लिए औपचारिक ऋण का महत्वपूर्ण स्रोत है और यह बिना गिरवी के लोन उपलब्ध कराता है। वहां तक कि, मुद्रा एनबीएफसी-एमएफआइ का इस्तेमाल एक महत्वपूर्ण चैनल के तौर पर करता

है ताकि शिशु कैटेगरी लोन के जरिये इन ग्राहकों तक पहुंचा जा सके। उत्तराखंड में, शिशु कैटेगरी लोन के तहत मुद्रा ने लगभग 500 करोड़ रुपये का लोन बांटा है। इसमें से, एनबीएफसी-एमएफआइ और स्मॉल फाइनेंस बैंकों ने साथ मिलकर कम आय वर्ग वाले ग्राहकों को 275 करोड़ रुपये के लोन वितरित किये हैं।" उत्तराखंड में 31 नियमित वित्तीय संस्थान हैं जिसमें 10 एनबीएफसी-एमएफआइ और 3 स्मॉल फाइनेंस बैंक शामिल हैं। एनबीएफसी-एमएफआइ का सकल लोन पोर्टफोलियो 327 करोड़ रुपये का है और यह 2 लाख घरों की जरूरतों को पूरा करते हैं। उत्तराखंड में वित्तीय समावेशन को राज्य में काम कर रहे बिजनेस कंसर्न-इंडेक्स, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, एसएचजी और सहकारी बैंकों का भी सहयोग मिला है। इस सम्मेलन में एनबीएफसी-एमएफआइ, स्मॉल फाइनेंस बैंक, क्षेत्रीय बैंकों के प्रतिनिधि और नीति निर्माताओं आदि ने शिरकत की। इस सम्मेलन में आने वाले प्रमुख वक्ताओं में शामिल थे।

Publication	Jan Aagaj
Edition	Dehradun
Date	13 th April, 2018
Page No.	03

उत्तराखण्ड में वित्तीय समावेशन की प्रगति और परिदृश्य पर सम्मेलन आयोजित

देहरादून। माइक्रोफाइनेंस इंस्टीट्यूट्स नेटवर्क (एमएफआइएन), एक स्व-विनामकीय संस्थान और उद्योग संगठन ने आज देहरादून में वित्तीय समावेशन पर राज्य के पहले सम्मेलन का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का मुख्य विषय था “उत्तराखण्ड में वित्तीय समावेशन की प्रगति और परिदृश्य”। अमित सिंह नेगी, सचिव (फाइनेंस) ने सम्मेलन में विशेष संबोधन दिया। इस सम्मेलन का उद्देश्य राज्य में वित्तीय समावेशन की स्थिति का विश्लेषण करना था। साथ ही इसमें मौजूद चुनौतियों एवं अवसरों पर भी चर्चा की गई। वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने में माइक्रोफाइनेंस एवं फिनटेक की भूमिका पर भी विचार-विमर्श हुआ। सुब्रत दास, प्रादेशिक निदेशक, आरबीआई देहरादून और डी.एन. मागर, सीजीएम नाबार्ड, उत्तराखण्ड सम्मेलन में पैनलिस्ट के तौर पर उपस्थित हुये। पैनल में शामिल होने वाले अन्य लोगों में राकेश दुबे, प्रेसिडेंट, एमएफआइएन और देवेश



सचदेव, वाइस प्रेसिडेंट, एमएफआइएन थे। अमित सिंह नेगी, सेक्रेटरी (फाइनेंस), उत्तराखण्ड के कहा की प्रति व्यक्ति की आय में बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने यह भी कहा की पहाड़ी इलाकों में असमानताएं हैं जिन्हें दूर किया जा सकता है। उन्होंने यह भी कहा की असमानताएं को सर्विस सेक्टर को भरावा दे कर दूर किया जा सकता है। उन्होंने यह भी कहा की पहाड़ी इलाकों में महिलाओं का बड़ा योगदान है। इसीलिए जब हम फाइनेंसियल इन्क्लूसिव

की बातकरते हैं तो हम महिलाओं को महत्वपूर्ण स्थान देते हैं।’ राकेश दुबे, एमएफआइएन के प्रेसिडेंट के अनुसार, “एनबीएफसी-एमएफआइएन, स्मॉल फाइनेंस बैंक और बैंकों जैसे वित्तीय संस्थानों ने राज्य में सरकार के वित्तीय समावेशन एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। विभिन्न रिपोर्टों के अनुसार, सबसे नया राज्य होने के बावजूद, उत्तराखण्ड वर्तमान में वित्तीय समावेशन के मामले में देश में 12वें स्थान पर है।

Publication	News Detail
Edition	Dehradun
Date	13 th April, 2018
Page No.	03

सार-संक्षेप....

उत्तराखंड में वित्तीय समावेशन की प्रगति और परिदृश्य पर सम्मेलन आयोजित



देहरादून। माइक्रोफाइनेंस इंस्टीट्यूशंस नेटवर्क (एमएफआईएन), एक स्व-विनामकीय संस्थान और उद्योग संगठन ने आज देहरादून में वित्तीय समावेशन पर राज्य के पहले सम्मेलन का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का मुख्य विषय था “उत्तराखंड में वित्तीय समावेशन की प्रगति और परिदृश्य”। अमित सिंह नेगी, सचिव (फाइनेंस) ने सम्मेलन में विशेष संबोधन दिया। इस सम्मेलन का उद्देश्य राज्य में वित्तीय समावेशन की स्थिति का विश्लेषण करना था। साथ ही इसमें मौजूद चुनौतियों एवं अवसरों पर भी चर्चा की गई। वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने में माइक्रोफाइनेंस एवं फिनटेक की भूमिका पर भी विचार-विमर्श हुआ। सुब्रत दास, प्रादेशिक निदेशक, आरबीआई देहरादून और डी.एन. मागर, सीजीएम नाबार्ड, उत्तराखंड सम्मेलन में पैनलिस्ट के तौर पर उपस्थित हुये। पैनल में शामिल होने वाले अन्य लोगों में राकेश दुबे, प्रेसिडेंट, एमएफआईएन और देवेश सचदेव, वाइस प्रेसिडेंट, एमएफआईएन थे। अमित सिंह नेगी, सेक्रेटरी (फाइनेंस), उत्तराखंड के कहा की प्रति व्यक्ति की आय में बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने यह भी कहा की पहाड़ी इलाकों में असमानताएं हैं जिन्हें दूर किया जा सकता है। उन्होंने यह भी कहा की असमानताएं को सर्विस सेक्टर को भरावा दे कर दूर किया जा सकता है। उन्होंने यह भी कहा की पहाड़ी इलाकों में महिलाओं का बड़ा योगदान है। इसीलिए जब हम फाइनेंसियल इन्क्लूसिव की बात करते हैं तो हम महिलाओं को महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। राकेश दुबे, एमएफआईएन के प्रेसिडेंट के अनुसार, “एनबीएफसी-एमएफआईएन, स्मॉल फाइनेंस बैंक और बैंकों जैसे वित्तीय संस्थानों ने राज्य में सरकार के वित्तीय समावेशन एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। विभिन्न रिपोर्टों के अनुसार, सबसे नया राज्य होने के बावजूद, उत्तराखंड वर्तमान में वित्तीय समावेशन के मामले में देश में 12वें स्थान पर है। हालांकि, यहां खासतौर से पहाड़ी जिलों में जहां 70 प्रतिशत आबादी निवास करती है, वित्तीय सेवाओं तक आसान पहुंच अभी भी उपलब्ध नहीं है, इस जरूरत को पूरा किया जाना जरूरी है।

Publication	Jan Bharat Mail
Edition	Dehradun
Date	13 th April, 2018
Page No.	12

वितीय समावेश पर सम्मेलन का आयोजन

देहरादून। माइक्रोफाइनेंस इंस्टीट्यूट्स नेटवर्क (एमएफआइएन), एक स्व-विनामकीय संस्थान और उद्योग संगठन, ने आज देहरादून में वित्तीय समावेशन पर राज्य के पहले सम्मेलन का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का मुख्य विषय था "उत्तराखंड में वित्तीय समावेशन की प्रगति और परिदृश्य"। श्री अमित सिंह नेगी, सचिव (फाइनेंस) ने सम्मेलन में विशेष संबोधन दिया। इस सम्मेलन का उद्देश्य राज्य में वित्तीय समावेशन की स्थिति का विश्लेषण करना था। साथ ही इसमें मौजूद चुनौतियों एवं अवसरों पर भी चर्चा की गई। वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने में माइक्रोफाइनेंस एवं फिनटेक की भूमिका पर भी विचार-विमर्श हुआ। श्री सुब्रत दास, प्रादेशिक निदेशक, आरबीआई देहरादून और श्री डी.एन. मागर, सीजीएम नाबार्ड,



उत्तराखंड सम्मेलन में पैनलिस्ट के तौर पर उपस्थित हुये। पैनल में शामिल होने वाले अन्य लोगों में श्री राकेश दुबे, प्रेसिडेंट, एमएफआइएन और श्री देवेश सचदेव, वाइस प्रेसिडेंट, एमएफआइएन थे। श्री अमित सिंह नेगी, सेक्रेटरी (फाइनेंस), उत्तराखंड के कहा की प्रति व्यक्ति की आय में बढ़ोतरी हुई है छ उन्होंने यह भी कहा की पहाड़ी इलाकों में

असमानताएं हैं जिन्हें दूर किया जा सकता है। उन्होंने यह भी कहा की असमानताएं को सर्विस सेक्टर को भरावा दे कर दूर किया जा सकता है। उन्होंने यह भी कहा की पहाड़ी इलाकों में महिलाओं का बड़ा योगदान है। इसीलिए जब हम फाइनेंसियल इन्क्लूसिव की बात करते हैं तो हम महिलाओं को महत्वपूर्ण स्थान देते हैं।

Publication	Doon Darpan
Edition	Dehradun
Date	13 th April, 2018
Page No.	12

रोड तथा रूसों बाईपास में पाकिंग

हुय परामिट निरस्त करने का

आधशासा आधकारा नगरपालिका

निर्देशा 15 पन

देहरादून 12 अप्रैल (एजेंसी)। माइक्रोफाइनेंस इंस्टीट्यूट्स नेटवर्क (एमएफआईएन), एक स्व-खिनामकीय संस्थान और उद्योग संगठन, ने आज देहरादून में वित्तीय समावेशन पर राज्य के पहले सम्मेलन का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का मुख्य विषय था “उत्तराखंड में वित्तीय समावेशन की प्रगति और परिदृश्य”। अमित सिंह नेगी, सचिव (फाइनेंस) ने सम्मेलन में विशेष संबोधन दिया। इस सम्मेलन का उद्देश्य राज्य में वित्तीय समावेशन की स्थिति का विश्लेषण करना था। साथ ही इसमें मौजूद चुनौतियों एवं अवसरों पर भी चर्चा की गई। वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने में माइक्रोफाइनेंस एवं फिनटेक की भूमिका पर भी विचार-विमर्श हुआ। सुब्रत दास, प्रादेशिक निदेशक, आरबीआई देहरादून और डी.एन. मागर, सीजीएम नाबार्ड, उत्तराखंड सम्मेलन में पैनलिस्ट के तौर पर उपस्थित हुये। पैनल में शामिल होने वाले अन्य लोगों में राकेश दुबे, प्रेसिडेंट, एमएफआईएन और देवेश सचदेव, वाइस प्रेसिडेंट, एमएफआईएन थे। अमित सिंह नेगी, सेक्रेटरी (फाइनेंस), उत्तराखंड के कहा की प्रति व्यक्ति की आय में बढ़ोतरी हुई है उन्होंने यह भी कहा की पहाड़ी इलाकों में असमानताएं हैं जिन्हें दूर किया जा सकता है उन्होंने यह भी कहा की असमानताएं को सर्विस सेक्टर को भरावा दे कर दूर किया जा सकता है उन्होंने यह भी कहा की पहाड़ी इलाकों में महिलाओं का बड़ा योगदान है। इसीलिए जब हम फाइनेंसियल इन्क्लूसिव की बात करते हैं तो हम महिलाओं को महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। “राकेश दुबे, एमएफआईएन के अनुसार, “एनबीएफसी-एमएफआईज, स्मॉल फाइनेंस बैंक और बैंकों जैसे वित्तीय संस्थानों ने राज्य में सरकार के वित्तीय समावेशन एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। विभिन्न रिपोर्टों के अनुसार, सबसे नया राज्य होने के बावजूद, उत्तराखंड वर्तमान में वित्तीय समावेशन के मामले में देश में 12वें स्थान पर है। हालांकि, यहां खासतौर से पहाड़ी जिलों में जहां 70 प्रतिशत आबादी निवास करती है, वित्तीय सेवाओं तक आसान पहुंच अभी भी उपलब्ध नहीं है, इस जरूरत को पूरा किया जाना जरूरी है। वित्तीय संस्थानों और लोगों दोनों द्वारा कई बाधाओं का सामना किया जा रहा है, जैसेकि सेवाएं प्रदान करने में आने वाला अधिक खर्च और वित्तीय साक्षरता का अभाव आदि। इसके लिए खोजपरक समाधानों की जरूरत है। फिनटेक इन कठिनाईयों से पार पाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। “माइक्रोफाइनेंस की भूमिका के बारे में उन्होंने आगे कहा, “राज्य में 35 प्रतिशत से अधिक आबादी गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रही है। माइक्रोफाइनेंस इस वर्ग के लिए औपचारिक ऋण का महत्वपूर्ण स्रोत है और यह बिना गिरवी के लोन उपलब्ध कराता है। यहां तक कि, मुद्रा एनबीएफसी-एमएफआई का इस्तेमाल एक महत्वपूर्ण चैनल के तौर पर करता है ताकि शिशु कैटेगरी लोन के जरिये इन ग्राहकों तक पहुंचा जा सके। उत्तराखंड में, शिशु कैटेगरी लोन के तहत मुद्रा ने लगभग 500 करोड़ रुपये का लोन बांटा है। इसमें से, एनबीएफसी-एमएफआई और स्मॉल फाइनेंस बैंकों ने साथ मिलकर कम आय वर्ग वाले ग्राहकों को 275 करोड़ रुपये के लोन वितरित किये हैं।”

Publication	Garhwal Post
Edition	Dehradun
Date	13 th April, 2018
Page No.	07

MFIN organises U'khand 'Finclave 2018', financial inclusion analysed

By OUR STAFF REPORTER

DEHRADUN, 12 Apr: Microfinance Institutions Network (MFIN), a self-regulatory organisation and an industry association, organised the state's first conclave around Financial Inclusion, here, today. The theme of the event was "Progress and Prospectus of Financial Inclusion in Uttarakhand".

Amit Singh Negi, Secretary (Finance), presented the special address at the conclave.

The aim of the conclave was to analyse status of financial inclusion in the state while deliberating upon the challenges and opportunities present in increasing its ambit. The discussions also revolved around the role of microfinance and fintech in fostering financial inclusion. Subrata Das, Regional Director, RBI, Dehradun, and DN Magar, CGM, NABARD, Uttarakhand, were among the panellists at the conclave. The panels also included Rakesh Dubey, President, MFIN and Devesh Sachdev, Vice President, MFIN.

Secretary Amit Singh Negi said that the per capita income of the state had increased. He also said that there were inequalities in the hilly areas, which could be overcome by encouraging the growth of the service sector. Women contributed significantly in the hill areas. "That is why when we talk about financial inclusion, we give more importance to women," he emphasised.

According to Rakesh Dubey, President, MFIN, "Financial entities such as NBFC-MFIs, Small Bank Finance and Banks have played an important role in furthering the financial inclusion agenda of the government in the state. According to the reports, despite being one of the youngest states Uttarakhand, today, ranks 12th in financial inclusion in the country. However, there are still gaps in easy accessibility to financial services especially in the hilly districts, where 70%



of the population resides, that need to be addressed. Both financial institutions and the population face hurdles such as higher cost of delivery of services and lack of financial literacy among others and require innovative solutions. Fintech can play a crucial role in addressing these difficulties."

On the role of microfinance, he added, "Over 35% of the population in the state lives under the poverty line.

Microfinance has been a crucial source of formal credit to this segment, providing collateral free for unsecured loans. In fact, MUDRA uses NBFC-MFIs as an important channel to reach out to these customers through Shishu category loans. In Uttarakhand, under Shishu category loans, MUDRA has disbursed around Rs 500 crore. Out of this, NBFC-MFIs and Small Finance Banks collectively have disbursed loans worth

Rs 275 Cr to low income segment customers."

Uttarakhand has 31 regulated financial institutions that include 10 NBFC-MFIs and 3 Small Finance Banks. NBFC-MFIs have Gross Loan Portfolio of Rs 327 Cr and cater to around 2 lakh households. The financial inclusion in the state has also been supported by business correspondents, Regional Rural Banks,

SHGs, and Cooperative Banks operational in the state.

The conference was attended by representatives of NBFC-MFIs, Small Finance Banks, regional banks and policy makers among others. Notable speakers at the conclave included Ramesh Kumar Pant, AGM, SLBC, Uttarakhand, NK Maini, Board Member, MUDRA & MFIN, and former DMD, SIDBI; Sanjay Agarwal, Chairman, Uttarakhand Gramin Bank; Navneet Kumar, VP Financial Inclusion & New Business, National Payments Corporation of India (NPFI); Dev Verma, COO, Satin Creditcare Network Ltd; Govind Singh, MD, Utkarsh Small Finance Bank and Subir Kumar Mukherjee, DGM, SBI Dehradun. On behalf of University of Petroleum and Energy Studies, Dr Deepankar Chhabra, Dr Sumeet Gupta and Dr Vinay also attended the event. University of Petroleum and Energy Studies was the knowledge partner of Uttarakhand FINCLAVE.

Minister Rekha Arya stresses on doubling farmers' incomes

By OUR STAFF REPORTER

DEHRADUN, 12 Apr: A review meeting chaired by the Child Welfare, Animal Husbandry, Fisheries Development (Independent Charge) Rekha Arya was held with the objective of doubling the income of farmers, at her Vidhan Sabha office, here, on Thursday. She directed the officials to focus on doubling the income of farmers and stressed on improving the breeds of animals. She urged

the officers to provide training and loans to the farmers through cooperatives to increase their income.

She wanted women to be deployed as 'Para-Vets' at the Nyay Panchayat level to improve the breed of the animals. The minister said that the work of 'Para-Vets' was being done by males, but there was need to train women, too, to provide veterinary services in the villages.

Stress would be laid on appointing 10 women 'Para Vets' in each of the nine hill

districts, who would be provided training in animal husbandry to increase self-employment. She also stressed on propagating meat from Uttarakhand as natural Himalayan meat, which would help in its sales as a brand name and in turn help the farmers. She said that a plan has been made in this regard by the department.

She sought formation of small societies interested in animal husbandry and these to be registered as cooperatives. Women would be given priority

in this area. Stress was laid on organising Animal Fairs and exhibitions, following the monsoons where seminars, display of agri-products would be the highlight of the event and the farmers involved in improving the breeds of the animals would be awarded.

Secretary, Animal Husbandry, R Meenakshi Sundaram, Director, Animal Husbandry Dr KK Joshi, Chief Executive Officer, Sheep Board, Dr Avinash Anand were present on the occasion.

Publication	Action India
Edition	Dehradun
Date	13 th April, 2018
Page No.	03

उत्तराखंड में वित्तीय समावेशन की प्रगति और परिदृश्य पर सम्मेलन आयोजित

देहरादून/एम्पान इंडिया ब्यूरो
माइक्रोफाइनेंस इंस्टीट्यूट्स नेटवर्क (एमएफआईएन), एक स्व-विनियमन संस्थान और उद्योग संगठन ने देहरादून में वित्तीय समावेशन पर राज्य के पहले सम्मेलन का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का मुख्य विषय था उत्तराखंड में वित्तीय समावेशन की प्रगति और परिदृश्य। अमित सिंह नेगी, सचिव (फाइनेंस) ने सम्मेलन में विशेष संबोधन दिया। इस सम्मेलन का उद्देश्य राज्य में वित्तीय समावेशन की स्थिति का विश्लेषण

करना था। साथ ही इसमें मौजूद चुनौतियों एवं अवसरों पर भी चर्चा की गई। वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने में माइक्रोफाइनेंस एवं फिनटेक की भूमिका पर भी विचार-विमर्श हुआ। सुब्रत दास, प्रादेशिक निदेशक, आरबीआई देहरादून और डी.एन. मारर, सीजीएम नाबाई, उत्तराखंड सम्मेलन में पैनलिस्ट के तौर पर उपस्थित हुए। पैनल में शामिल होने वाले अन्य लोगों में राकेश दुबे, प्रेसिडेंट, एमएफआईएन और देवेश सचदेव, वाइस प्रेसिडेंट, एमएफआईएन थे। अमित सिंह

विभिन्न रिपोर्टों के अनुसार, सबसे नया राज्य होने के बावजूद उत्तराखंड वर्तमान में वित्तीय समावेशन के मामले में देश में 12वें स्थान पर है

नेगी, सेक्रेटरी (फाइनेंस), उत्तराखंड के कहा की प्रति व्यक्ति की आय में भड़ोली हुई है। उन्होंने यह भी कहा की पहाड़ी इलाकों में असमानताएँ हैं जिन्हें दूर किया जा सकता है। उन्होंने यह भी कहा की असमानताएँ को सर्विस सेक्टर को भरवा



वित्तीय समावेशन की प्रगति और परिदृश्य पर आयोजित सम्मेलन में मंचासीन कक्षा।

दे कर दूर किया जा सकता है। उन्होंने यह भी कहा की पहाड़ी इलाकों में महिलाओं

का बड़ा योगदान है। इसलिए जब हम फाइनेंसियल इन्क्लूषिव की बात करते हैं तो हम महिलाओं को महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। राकेश दुबे, एमएफआईएन के प्रेसिडेंट के अनुसार, एनबीएफसी-एमएफआईएन, स्मॉल फाइनेंस बैंक और बैंकों जैसे वित्तीय संस्थानों ने राज्य में सरकार के वित्तीय समावेशन एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। विभिन्न रिपोर्टों के अनुसार, सबसे नया राज्य होने के बावजूद, उत्तराखंड वर्तमान में वित्तीय समावेशन के मामले में देश में

12वें स्थान पर है। हालाँकि, यहाँ खासतौर से पहाड़ी जिलों में जहाँ 70 प्रतिशत आबादी निवास करती है, वित्तीय सेवाओं तक आसान पहुँच अभी भी उपलब्ध नहीं है, इस ज़रूरत को पूरा किया जाना जरूरी है। वित्तीय संस्थानों और लोगों दोनों द्वारा कई बाधाओं का सामना किया जा रहा है, जैसेकि सेवाएँ प्रदान करने में आने वाला अधिक खर्च और वित्तीय साक्षरता का अभाव आदि। इसके लिए खोजपरक समाधानों की जरूरत है।

Publication	Saksham Uttarakhand
Edition	Dehradun
Date	13 th April, 2018
Page No.	05

उत्तराखंड में वित्तीय समावेशन की प्रगति और परिदृश्य पर सम्मेलन आयोजित

देहरादून। माइक्रोफाइनेंस इंस्टीट्यूट्स नेटवर्क (एमएफआईएन), एक स्व-विनामकीय संस्थान और उद्योग संगठन ने आज देहरादून में वित्तीय समावेशन पर राज्य के पहले सम्मेलन का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का मुख्य विषय था “उत्तराखंड में वित्तीय समावेशन की प्रगति और परिदृश्य”। अमित सिंह नेगी, सचिव (फाइनेंस) ने सम्मेलन में विशेष संबोधन दिया। इस सम्मेलन का उद्देश्य राज्य में वित्तीय समावेशन की स्थिति का विश्लेषण करना था। साथ ही इसमें मौजूद चुनौतियों एवं अवसरों पर भी चर्चा की गई। वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने में माइक्रोफाइनेंस एवं फिन्टेक की भूमिका पर भी विचार-विमर्श हुआ। सुब्रत दास, प्रादेशिक निदेशक, आरबीआई देहरादून और डी.एन. मागर, सीजीएम नाबार्ड, उत्तराखंड सम्मेलन में पैनलिस्ट के तौर पर उपस्थित हुये। पैनल में शामिल होने वाले अन्य लोगों में राकेश दुबे, प्रेसिडेंट, एमएफआईएन और देवेश सचदेव, वाइस

प्रेसिडेंट, एमएफआईएन थे। अमित सिंह नेगी, सेक्रेटरी (फाइनेंस), उत्तराखंड के कहा की प्रति व्यक्ति की आय में भद्रोत्तरी हुई है। उन्होंने यह भी कहा की पहाड़ी इलाकों में असमानताएं हैं जिन्हें दूर किया जा सकता है। उन्होंने यह भी कहा की असमानताएं को सर्विस सेक्टर को भरावा दे कर दूर किया जा सकता है। उन्होंने यह भी कहा की पहाड़ी इलाकों में महिलाओं का बड़ा योगदान है। इसीलिए जब हम फाइनेंसियल इन्क्लूसिव की बात करते हैं तो हम महिलाओं को महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। राकेश दुबे, एमएफआईएन के प्रेसिडेंट के अनुसार, “एनबीएफसी-एमएफआईएन, स्मॉल फाइनेंस बैंक और बैंकों जैसे वित्तीय संस्थानों ने राज्य में सरकार के वित्तीय समावेशन एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। विभिन्न रिपोर्टों के अनुसार, सबसे नया राज्य होने के बावजूद, उत्तराखंड वर्तमान में वित्तीय समावेशन के मामले में देश में 12वें स्थान पर है।

Publication	Pradhan Times
Edition	Dehradun
Date	13 th April, 2018
Page No.	06

उत्तराखंड में वित्तीय समावेशन की प्रगति और परिदृश्य पर सम्मेलन आयोजित

देहरादून। माइक्रोफाइनेंस इंस्टीट्यूट्स नेटवर्क (एमएफआईएन), एक स्व-विनामकीय संस्थान और उद्योग संगठन ने आज देहरादून में वित्तीय समावेशन पर राज्य के पहले सम्मेलन का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का मुख्य विषय था “उत्तराखंड में वित्तीय समावेशन की प्रगति और परिदृश्य”। अमित सिंह नेगी, सचिव (फाइनेंस) ने सम्मेलन में विशेष संबोधन दिया। इस सम्मेलन का उद्देश्य राज्य में वित्तीय समावेशन की स्थिति का विश्लेषण करना था। साथ ही इसमें मौजूद चुनौतियों एवं अवसरों पर भी चर्चा की गई। वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने में माइक्रोफाइनेंस एवं फिन्टेक की भूमिका पर भी विचार-विमर्श हुआ। सुब्रत दास, प्रादेशिक निदेशक, आरबीआई देहरादून और डी.एन. मागर, सीजीएम नाबार्ड, उत्तराखंड सम्मेलन में पैनलिस्ट के तौर पर उपस्थित हुये। पैनल में शामिल होने वाले अन्य लोगों में राकेश दुबे, प्रेसिडेंट, एमएफआईएन और देवेश सचदेव, वाइस प्रेसिडेंट, एमएफआईएन थे। अमित सिंह नेगी, सेक्रेटरी (फाइनेंस), उत्तराखंड के कहा की प्रति व्यक्ति की आय में भद्रोत्तरी हुई है। उन्होंने यह भी कहा की पहाड़ी इलाकों में असमानताएं हैं जिन्हें दूर किया

जा सकता है। उन्होंने यह भी कहा की असमानताएं को सर्विस सेक्टर को भरावा दे कर दूर किया जा सकता है। उन्होंने यह भी कहा की पहाड़ी इलाकों में महिलाओं का बड़ा योगदान है। इसीलिए जब हम फाइनेंसियल इन्क्लूसिव की बात करते हैं तो हम महिलाओं को महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। राकेश दुबे, एमएफआईएन के प्रेसिडेंट के अनुसार, “एनबीएफसी-एमएफआईएन, स्मॉल फाइनेंस बैंक और बैंकों जैसे वित्तीय संस्थानों ने राज्य में सरकार के वित्तीय समावेशन एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। विभिन्न रिपोर्टों के अनुसार, सबसे नया राज्य होने के बावजूद, उत्तराखंड वर्तमान में वित्तीय समावेशन के मामले में देश में 12वें स्थान पर है। हालांकि, यहां खासतौर से पहाड़ी जिलों में जहां 70 प्रतिशत आबादी निवास करती है, वित्तीय सेवाओं तक आसान पहुंच अभी भी उपलब्ध नहीं है, इस जरूरत को पूरा किया जाना जरूरी है। वित्तीय संस्थानों और लोगों दोनों द्वारा कई बाधाओं का सामना किया जा रहा है, जैसेकि सेवाएं प्रदान करने में आने वाला अधिक खर्च और वित्तीय साक्षरता का अभाव आदि। इसके लिए खोजपरक समाधानों की जरूरत है।

Publication	Veer Arjun
Edition	Dehradun
Date	13 th April, 2018
Page No.	05

उत्तराखण्ड में वित्तीय समावेशन की प्रगति और परिदृश्य पर सम्मेलन आयोजित

वीर अर्जुन संवाददाता
देहरादून, 13। माइक्रोफाइनेंस इंस्टीट्यूट्स नेटवर्क (एमएफआईएन), एक स्व-विनामकीय संस्थान और उद्योग संगठन ने आज देहरादून में वित्तीय समावेशन पर राज्य के पहले सम्मेलन का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का मुख्य विषय था 'उत्तराखण्ड में वित्तीय समावेशन की प्रगति और परिदृश्य'। अमित सिंह नेगी, सचिव (फाइनेंस) ने सम्मेलन में विशेष संबोधन दिया। इस सम्मेलन का उद्देश्य राज्य में वित्तीय समावेशन की स्थिति का विश्लेषण करना था। साथ ही इसमें मौजूद चुनौतियों एवं अवसरों पर भी चर्चा की गई। वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने में माइक्रोफाइनेंस एवं फिनटेक की भूमिका पर भी विचार-विमर्श हुआ। सुब्रत दास, प्रादेशिक निदेशक, आरबीआई देहरादून और डी.एन. मार्गर, सीजीएम नाबार्ड, उत्तराखण्ड सम्मेलन में पैनेलिस्ट के तौर पर उपस्थित हुये। पैनल में शामिल होने वाले अन्य लोगों में राकेश दुबे, प्रेसिडेंट, एमएफआईएन और देवे



वित्तीय समावेशन की प्रगति और परिदृश्य पर आयोजित सम्मेलन में मंचासीन वर्तमा।

सचदेव, वाइस प्रेसिडेंट, एमएफआईएन थे। अमित सिंह नेगी, सेक्रेटरी (फाइनेंस), उत्तराखण्ड के कहा को प्रति व्यक्ति की आय में भरोतरी हुई है। उन्होंने यह भी कहा की पहाडी इलाको में असमानताएं हैं जिन्हें दूर किया जा सकता है। उन्होंने यह भी

कहा की असमानताएं को सर्विस सेक्टर को भरावा दे कर दूर कियाजा सकता है। उन्होंने यह भी कहा की पहाडी इलाको में महिलाओं का बडा योगदान है। इसीलिए जब हम फाइनेंसियल इन्क्लूसिव की बातकरते है तो हम महिलाओं को महत्वपूर्ण स्थान

देते है। राकेश दुबे, एमएफआईएन के प्रेसिडेंट के अनुसार, 'एनबीएफसी-एमएफआईएन, स्मॉल फाइनेंस बैंक और बैंकों जैसे वित्तीय संस्थानों ने राज्य में सरकार के वित्तीय समावेशन एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। विभिन्न

रिपोर्टों के अनुसार, सबसे नया राज्य होने के बावजूद, उत्तराखण्ड वर्तमान में वित्तीय समावेशन के मामले में देश में 12वें स्थान पर है।

हालांकि, यहां खासतौर से पहाडी जिलों में जहां 70 प्रतिशत आबादी निवास करती है, वित्तीय सेवाओं तक आसान पहुंच अभी भी उपलब्ध नहीं है, इस जरूरत को पूरा किया जाना जरूरी है। वित्तीय संस्थानों और लोगों दोनों द्वारा कई बाधाओं का सामना किया जा रहा है, जैसेकि सेवायें प्रदान करने में आने वाला अधिक खर्च और वित्तीय साक्षरता का अभाव आदि। इसके लिए खोजपरक समाधानों की जरूरत है। फिनटेक इन चुनौतियों से पार पाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। 'माइक्रोफाइनेंस की भूमिका के बारे में उन्होंने आगे कहा, 'राज्य में 35 प्रतिशत से अधिक आबादी गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रही है। माइक्रोफाइनेंस इस वर्ग के लिए औपचारिक ऋण का महत्वपूर्ण स्रोत है और यह बिना गिरवी के लोन उपलब्ध कराता है।

Publication	Uttar Bharat Live
Edition	Dehradun
Date	13 th April, 2018
Page No.	07

एमएफआइएन ने फिनक्लेव का किया आयोजन

देहरादून। माइक्रोफाइनेंस इंस्टीट्यूट्स नेटवर्क एमएफआइएन एक स्व विनामकीय संस्थान और उद्योग संगठन ने आज देहरादून में वित्तीय समावेशन पर राज्य के पहले सम्मेलन का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का मुख्य विषय था उत्तराखंड में वित्तीय समावेशन की प्रगति और परिदृश्य। अमित सिंह नेगी सचिव फाइनेंस ने सम्मेलन में विशेष संबोधन दिया। इस सम्मेलन का उद्देश्य राज्य में वित्तीय समावेशन की स्थिति का विश्लेषण करना था। साथ ही इसमें मौजूद चुनौतियों एवं अवसरों पर भी चर्चा की गई। वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने में माइक्रोफाइनेंस एवं फिनटेक की भूमिका पर भी विचार विमर्श हुआ। सुब्रत दास प्रादेशिक निदेशक आरबीआई देहरादून और डीएन मागर सीजीएम नाबार्ड उत्तराखंड सम्मेलन में पैनलिस्ट के तौर पर उपस्थित हुये।

ONLINE COVERAGE

Website	Gadh Samvedna
Date	12 th April, 2018
Link	http://gadhsamvedna.com/उत्तराखंड-में-वित्तीय-सम/



The image shows a screenshot of the Gadhsamvedna website. The header features the title 'गढ़ संवेदना' (Gadh Samvedna) in large red Hindi characters, with 'डेली न्यूज़ पोर्टल' (Daily News Portal) in a black box below it. The navigation bar includes links for HOME, BREAKING NEWS, NATIONAL, **UTTARAKHAND** (highlighted in red), ENTERTAINMENT, SPORTS, and ED. Below the navigation bar is a photograph of a panel discussion. Five men are seated on a stage in front of a large screen. The screen displays the text 'Financial Inclusion in Uttarakhand' and 'An Imperative for Inclusive Development'. The men are dressed in business attire, and there are water bottles and papers on the table in front of them.

उत्तराखंड में वित्तीय समावेशन की प्रगति और परिदृश्य पर
सम्मेलन आयोजित

देहरादून। माइक्रोफाइनेंस इंस्टीट्यूट्स नेटवर्क (एमएफआइएन), एक स्व-विनामकीय संस्थान और उद्योग संगठन ने आज देहरादून में वित्तीय समावेशन पर राज्य के पहले सम्मेलन का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का मुख्य विषय था "उत्तराखंड में वित्तीय समावेशन की प्रगति और परिदृश्य"। अमित सिंह नेगी, सचिव (फाइनेंस) ने सम्मेलन में विशेष संबोधन दिया। इस सम्मेलन का उद्देश्य राज्य में वित्तीय समावेशन की स्थिति का विश्लेषण करना था। साथ ही इसमें मौजूद चुनौतियों एवं अवसरों पर भी चर्चा की गई। वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने में माइक्रोफाइनेंस एवं फिनटेक की भूमिका पर भी विचार-विमर्श हुआ। सुब्रत दास, प्रादेशिक निदेशक, आरबीआई देहरादून और डी.एन. मागर, सीजीएम नाबार्ड, उत्तराखंड सम्मेलन में पैनलिस्ट के तौर पर उपस्थित हुये। पैनल में शामिल होने वाले अन्य लोगों में राकेश दुबे, प्रेसिडेंट, एमएफआइएन और देवेश सचदेव, वाइस प्रेसिडेंट, एमएफआइएन थे। अमित सिंह नेगी, सेक्रेटरी (फाइनेंस), उत्तराखंड के कहा की प्रति व्यक्ति की आय में भ्रूतरी हुई है। उन्होंने यह भी कहा की पहाड़ी इलाकों में असमानताएं हैं जिन्हें दूर किया जा सकता है। उन्होंने यह भी कहा की असमानताएं को सर्विस सेक्टर को भरावा दे कर दूर किया जा सकता है। उन्होंने यह भी कहा की पहाड़ी इलाकों में महिलाओं का बड़ा योगदान है। इसीलिए जब हम फाइनेंसियल इन्क्लूसिव की बात करते हैं तो हम महिलाओं को महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। राकेश दुबे, एमएफआइएन के प्रेसिडेंट के अनुसार, "एनबीएफसी-एमएफआइएन, स्मॉल फाइनेंस बैंक और बैंकों जैसे वित्तीय संस्थानों ने राज्य में सरकार के वित्तीय समावेशन एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। विभिन्न रिपोर्टों के अनुसार, सबसे नया राज्य होने के बावजूद, उत्तराखंड वर्तमान में वित्तीय समावेशन के मामले में देश में 12वें स्थान पर है। हालांकि, यहां खासतौर से पहाड़ी जिलों में जहां 70 प्रतिशत आबादी निवास करती है, वित्तीय सेवाओं तक आसान पहुंच अभी भी उपलब्ध नहीं है, इस जरूरत को पूरा किया जाना जरूरी है। वित्तीय संस्थानों और लोगों दोनों द्वारा कई बाधाओं का सामना किया जा रहा है, जैसेकि सेवाएं प्रदान करने में आने वाला अधिक खर्च और वित्तीय साक्षरता का अभाव आदि। इसके लिए खोजपरक समाधानों की जरूरत है। फिनटेक इन कठिनाईयों से पार पाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं।" माइक्रोफाइनेंस की भूमिका के बारे में उन्होंने आगे कहा, "राज्य में 35 प्रतिशत से अधिक आबादी गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रही है। माइक्रोफाइनेंस इस वर्ग के लिए औपचारिक ऋण का महत्वपूर्ण स्रोत है और यह बिना गिरवी के लोन उपलब्ध कराता है। यहां तक कि, मुद्रा एनबीएफसी-एमएफआइ का इस्तेमाल एक महत्वपूर्ण चैनल के तौर पर करता है ताकि शिशु कैटेगरी लोन के जरिये इन ग्राहकों तक पहुंचा जा सके। उत्तराखंड में, शिशु कैटेगरी लोन के तहत मुद्रा ने लगभग 500 करोड़ रुपये का लोन बांटा है। इसमें से, एनबीएफसी-एमएफआइ और स्मॉल फाइनेंस बैंकों ने साथ मिलकर कम आय वर्ग वाले ग्राहकों को 275 करोड़ रुपये के लोन वितरित किये हैं।"

उत्तराखंड में 31 नियमित वित्तीय संस्थान हैं जिसमें 10 एनबीएफसी-एमएफआइ और 3 स्मॉल फाइनेंस बैंक शामिल हैं। एनबीएफसी-एमएफआइ का सकल लोन पोर्टफोलियो 327 करोड़ रुपये का है और यह 2 लाख घरों की जरूरतों को पूरा करते हैं। उत्तराखंड में वित्तीय समावेशन को राज्य में काम कर रहे बिजनेस कॉरिस्पॉन्डेंट्स, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, एसएचजी और सहकारी बैंकों का भी सहयोग मिला है।

इस सम्मेलन में एनबीएफसी-एमएफआइ, स्मॉल फाइनेंस बैंक, क्षेत्रीय बैंकों के प्रतिनिधि और नीति निर्माताओं आदि ने शिरकत की। इस सम्मेलन में आने वाले प्रमुख वक्ताओं में शामिल थे रमेश कुमार पंत, एजीएम एसएलबीसी उत्तराखंड, एन.के. मैनी, बोर्ड सदस्य मुद्रा एंड एमएफआइएन और पूर्व डीएमडी, सिडबी; संजय अग्रवाल, चेयरमैन, उत्तराखंड ग्रामीण बैंक; नवनीत कुमार, वीपी, वित्तीय समावेशन एवं नये व्यावसाय, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई); श्रीदेव वर्मा, सीओओ, सैटिन क्रेडिटकेयर नेटवर्क लिमिटेड; गोविंद सिंह, एमडी, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक और सुबीर कुमार मुखर्जी, डीजीएम, एसबीआई देहरादून। यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी स्टडीज इस सम्मेलन का नॉलेज पार्टनर था द्र. डॉ. दीपांकर छाबरा, डॉ. सुमीत गुप्ता और डॉ. विनययूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी स्टडीज के तरफ से इस सम्मेलन में शामिल थे।

Website	Pehchan Express
Date	12 th April, 2018
Link	http://pehchanexpress.com/वित्तीय-समावेशन-की-प्रगत/

पहचान एक्सप्रेस  पहचान सच कही....

 बच्चों को भीख नहीं अपनो देर में नहीं पढ़े और पढ़ाए

पहचान एक्सप्रेस

NATIONAL | UTTARAKHAND | SPORTS | ENTERTAINMENT | AJAB-GAJAB | PAHAL | PEHCHAN

BREAKING NEWS: 2, 2018 बेटी बचाओ से क्या अब हम बलात्कारी बचाओ हो गए: गंभीर - Thursday

वित्तीय समावेशन की प्रगति और परिदृश्य पर उत्तराखण्ड में हुआ सम्मेलन आयोजित

Posted by [pehchanadmin](#) on Thursday, April 12, 2018 · [Leave a Comment](#)



FINCLAVE 2018
Financial Inclusion in Uttarakhand
An Imperative for Inclusive Development

देहरादून। माइक्रोफाइनेंस इंस्टीट्यूट्स नेटवर्क (एमएफआइएन), एक स्व-विनामकीय संस्थान और उद्योग संगठन ने आज देहरादून में वित्तीय समावेशन पर राज्य के पहले सम्मेलन का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का मुख्य विषय था "उत्तराखंड में वित्तीय समावेशन की प्रगति और परिदृश्य"। अमित सिंह नेगी, सचिव (फाइनेंस) ने सम्मेलन में विशेष संबोधन दिया। इस सम्मेलन का उद्देश्य राज्य में वित्तीय समावेशन की स्थिति का विश्लेषण करना था। साथ ही इसमें मौजूद चुनौतियों एवं अवसरों पर भी चर्चा की गई। वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने में माइक्रोफाइनेंस एवं फिनटेक की भूमिका पर भी विचार-विमर्श हुआ। सुब्रत दास, प्रादेशिक निदेशक, आरबीआई देहरादून और डी.एन. मागर, सीजीएम नाबार्ड, उत्तराखंड सम्मेलन में पैनलिस्ट के तौर पर उपस्थित हुये। पैनल में शामिल होने वाले अन्य लोगों में राकेश दुबे, प्रेसिडेंट, एमएफआइएन और देवेश सचदेव, वाइस प्रेसिडेंट, एमएफआइएन थे। अमित सिंह नेगी, सेक्रेटरी (फाइनेंस), उत्तराखंड के कहां की प्रति व्यक्ति की आय में भड़ोतरी हुई है। उन्होंने यह भी कहा की पहाड़ी इलाकों में असमानताएं हैं जिन्हें दूर किया जा सकता है। उन्होंने यह भी कहा की असमानताएं को सर्विस सेक्टर को भरावा दे कर दूर किया जा सकता है। उन्होंने यह भी कहा की पहाड़ी इलाकों में महिलाओं का बड़ा योगदान है। इसीलिए जब हम फाइनेंसियल इन्क्लूसिव की बातकरते हैं तो हम महिलाओं को महत्वपूर्ण स्थान देते हैं।" राकेश दुबे, एमएफआइएन के प्रेसिडेंट के अनुसार, "एनबीएफसी-एमएफआइ, स्मॉल फाइनेंस बैंक और बैंकों जैसे वित्तीय संस्थानों ने राज्य में सरकार के वित्तीय समावेशन एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। विभिन्न रिपोर्टों के अनुसार, सबसे नया राज्य होने के बावजूद, उत्तराखंड वर्तमान में वित्तीय समावेशन के मामले में देश में 12वें स्थान पर है। हालांकि, यहां खासतौर से पहाड़ी जिलों में जहां 70 प्रतिशत आबादी निवास करती है, वित्तीय सेवाओं तक आसान पहुंच अभी भी उपलब्ध नहीं है, इस जरूरत को पूरा किया जाना जरूरी है। वित्तीय संस्थानों और लोगों दोनों द्वारा कई बाधाओं का सामना किया जा रहा है, जैसेकि सेवायें प्रदान करने में आने वाला अधिक खर्च और वित्तीय साक्षरता का अभाव आदि। इसके लिए खोजपरक समाधानों की जरूरत है। फिनटेक इन कठिनाईयों से पार पाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं।" माइक्रोफाइनेंस की भूमिका के बारे में उन्होंने आगे कहा, "राज्य में 35 प्रतिशत से अधिक आबादी गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रही है। माइक्रोफाइनेंस इस वर्ग के लिए औपचारिक ऋण का महत्वपूर्ण स्रोत है और यह बिना गिरवी के लोन उपलब्ध कराता है। यहां तक कि, मुद्रा एनबीएफसी-एमएफआइ का इस्तेमाल एक महत्वपूर्ण चैनल के तौर पर करता है ताकि शिशु कैटेगरी लोन के जरिये इन ग्राहकों तक पहुंचा जा सके। उत्तराखंड में, शिशु कैटेगरी लोन के तहत मुद्रा ने लगभग 500 करोड़ रुपये का लोन बांटा है। इसमें से, एनबीएफसी-एमएफआइ और स्मॉल फाइनेंस बैंकों ने साथ मिलकर कम आय वर्ग वाले ग्राहकों को 275 करोड़ रुपये के लोन वितरित किये हैं।" उत्तराखंड में 31 नियमित वित्तीय संस्थान हैं जिसमें 10 एनबीएफसी-एमएफआइ और 3 स्मॉल फाइनेंस बैंक शामिल हैं। एनबीएफसी-एमएफआइ का सकल लोन पोर्टफोलियो 327 करोड़ रुपये का है और यह 2 लाख घरों की जरूरतों को पूरा करते हैं। उत्तराखंड में वित्तीय समावेशन को राज्य में काम कर रहे बिजनेस कॉरिस्पॉन्डेंट्स, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, एसएचजी और सहकारी बैंकों का भी सहयोग मिला है। इस सम्मेलन में एनबीएफसी-एमएफआइ, स्मॉल फाइनेंस बैंक, क्षेत्रीय बैंकों के प्रतिनिधि और नीति निर्माताओं आदि ने शिरकत की। इस सम्मेलन में आने वाले प्रमुख वक्ताओं में शामिल थे रमेश कुमार पंत, एजीएम एसएलबीसी उत्तराखंड, एन.के. मैनी, बोर्ड सदस्य मुद्रा एंड एमएफआइएन और पूर्व डीएमडी, सिडबी; संजय अग्रवाल, चेयरमैन, उत्तराखंड ग्रामीण बैंक; नवनीत कुमार, वीपी, वित्तीय समावेशन एवं नये व्यावसाय, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई); श्रीदेव वर्मा, सीओओ, सैटिन क्रेडिटकेयर नेटवर्क लिमिटेड; गोविंद सिंह, एमडी, उल्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक और सुबीर कुमार मुखर्जी, डीजीएम, एसबीआई देहरादून। यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी स्टडीज इस सम्मेलन का नॉलेज पार्टनर था व डॉ. दीपांकर छाबरा, डॉ. सुमीत गुप्ता और डॉ. विनययूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी स्टडीज के तरफ से इस सम्मेलन में शामिल थे।

Website	News Detail
Date	12 th April, 2018
Link	http://newsdetail.in/उत्तराखंड-में-वित्तीय-सम/




[HOME](#)
[BREAKING NEWS](#)
[UTTARAKHAND](#)
[NATIONAL](#)
[TECHNOLOGY](#)
[SPORTS](#)
[POLITICS](#)

[Breaking News](#)
[» मुख्यमंत्री ने देवप्र](#)



Financial Inclusion in Uttarakhand
An Imperative for Inclusive Development

उत्तराखंड में वित्तीय समावेशन की प्रगति और परिदृश्य पर सम्मेलन आयोजित

देहरादून। माइक्रोफाइनेंस इंस्टीट्यूट्स नेटवर्क (एमएफआइएन), एक स्व-विनामकीय संस्थान और उद्योग संगठन ने आज देहरादून में वित्तीय समावेशन पर राज्य के पहले सम्मेलन का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का मुख्य विषय था "उत्तराखंड में वित्तीय समावेशन की प्रगति और परिदृश्य"। अमित सिंह नेगी, सचिव (फाइनेंस) ने सम्मेलन में विशेष संबोधन दिया। इस सम्मेलन का उद्देश्य राज्य में वित्तीय समावेशन की स्थिति का विश्लेषण करना था। साथ ही इसमें मौजूद चुनौतियों एवं अवसरों पर भी चर्चा की गई। वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने में माइक्रोफाइनेंस एवं फिनटेक की भूमिका पर भी विचार-विमर्श हुआ। सुब्रत दास, प्रादेशिक निदेशक, आरबीआई देहरादून और डी.एन. मागर, सीजीएम नाबार्ड, उत्तराखंड सम्मेलन में पैनलिस्ट के तौर पर उपस्थित हुये। पैनल में शामिल होने वाले अन्य लोगों में राकेश दुबे, प्रेसिडेंट, एमएफआइएन और देवेश सचदेव, वाइस प्रेसिडेंट, एमएफआइएन थे। अमित सिंह नेगी, सेक्रेटरी (फाइनेंस), उत्तराखंड के कहा की प्रति व्यक्ति की आय में भद्रोत्तरी हुई है। उन्होंने यह भी कहा की पहाड़ी इलाकों में असमानताएं हैं जिन्हें दूर किया जा सकता है। उन्होंने यह भी कहा की असमानताएं को सर्विस सेक्टर को भरावा दे कर दूर किया जा सकता है। उन्होंने यह भी कहा की पहाड़ी इलाकों में महिलाओं का बड़ा योगदान है। इसीलिए जब हम फाइनेंसियल इन्क्लूसिव की बात करते हैं तो हम महिलाओं को महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। राकेश दुबे, एमएफआइएन के प्रेसिडेंट के अनुसार, "एनबीएफसी-एमएफआइएन, स्मॉल फाइनेंस बैंक और बैंकों जैसे वित्तीय संस्थानों ने राज्य में सरकार के वित्तीय समावेशन एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। विभिन्न रिपोर्टों के अनुसार, सबसे नया राज्य होने के बावजूद, उत्तराखंड वर्तमान में वित्तीय समावेशन के मामले में देश में 12वें स्थान पर है। हालांकि, यहां खासतौर से पहाड़ी जिलों में जहां 70 प्रतिशत आबादी निवास करती है, वित्तीय सेवाओं तक आसान पहुंच अभी भी उपलब्ध नहीं है, इस जरूरत को पूरा किया जाना जरूरी है। वित्तीय संस्थानों और लोगों दोनों द्वारा कई बाधाओं का सामना किया जा रहा है, जैसेकि सेवायें प्रदान करने में आने वाला अधिक खर्च और वित्तीय साक्षरता का अभाव आदि। इसके लिए खोजपरक समाधानों की जरूरत है। फिनटेक इन कठिनाईयों से पार पाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं।" माइक्रोफाइनेंस की भूमिका के बारे में उन्होंने आगे कहा, "राज्य में 35 प्रतिशत से अधिक आबादी गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रही है। माइक्रोफाइनेंस इस वर्ग के लिए औपचारिक ऋण का महत्वपूर्ण स्रोत है और यह बिना गिरवी के लोन उपलब्ध कराता है। यहां तक कि, मुद्रा एनबीएफसी-एमएफआइ का इस्तेमाल एक महत्वपूर्ण चैनल के तौर पर करता है ताकि शिशु कैटेगरी लोन के जरिये इन ग्राहकों तक पहुंचा जा सके। उत्तराखंड में, शिशु कैटेगरी लोन के तहत मुद्रा ने लगभग 500 करोड़ रुपये का लोन बांटा है। इसमें से, एनबीएफसी-एमएफआइ और स्मॉल फाइनेंस बैंकों ने साथ मिलकर कम आय वर्ग वाले ग्राहकों को 275 करोड़ रुपये के लोन वितरित किये हैं।"

उत्तराखंड में 31 नियमित वित्तीय संस्थान हैं जिसमें 10 एनबीएफसी-एमएफआइ और 3 स्मॉल फाइनेंस बैंक शामिल हैं। एनबीएफसी-एमएफआइ का सकल लोन पोर्टफोलियो 327 करोड़ रुपये का है और यह 2 लाख घरों की जरूरतों को पूरा करते हैं। उत्तराखंड में वित्तीय समावेशन को राज्य में काम कर रहे बिजनेस कॉरिस्पॉन्डेंट्स, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, एसएचजी और सहकारी बैंकों का भी सहयोग मिला है। इस सम्मेलन में एनबीएफसी-एमएफआइ, स्मॉल फाइनेंस बैंक, क्षेत्रीय बैंकों के प्रतिनिधि और नीति निर्माताओं आदि ने शिरकत की। इस सम्मेलन में आने वाले प्रमुख वक्ताओं में शामिल थे रमेश कुमार पंत, एजीएम एसएलबीसी उत्तराखंड, एन.के. मैनी, बोर्ड सदस्य मुद्रा एंड एमएफआइएन और पूर्व डीएमडी, सिडबी; संजय अग्रवाल, चेयरमैन, उत्तराखंड ग्रामीण बैंक; नवनीत कुमार, वीपी, वित्तीय समावेशन एवं नये व्यावसाय, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई); श्रीदेव वर्मा, सीओओ, सेटिन क्रेडिटकेयर नेटवर्क लिमिटेड; गोविंद सिंह, एमडी, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक और सुबीर कुमार मुखर्जी, डीजीएम, एसबीआई देहरादून। यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी स्टडीज इस सम्मेलन का नॉलेज पार्टनर था छ डॉ. दीपांकर छाबरा, डॉ. सुमीत गुप्ता और डॉ. विनययूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी स्टडीज के तरफ से इस सम्मलेन में शामिल थे।